डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जनवरी, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 जनवरी, 2022

| वर्ष 65 | अंक 16 | भोपाल | 16 जनवरी, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

आत्म-निर्भर भारत बनाने में मध्यप्रदेश के युवा निभाएंगे भूमिका – मुख्यमंत्री श्री चौहान

बीते दो माह में सवा पाँच लाख युवाओं को विभिन्न योजनाओं में रोजगार

प्रत्येक माह मनाया जाएगा रोजगार दिवस हितग्राहियों को हित-लाभ वितरण, मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्म-निर्भर भारत और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में युवा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। रोजगार आज एक प्रमुख आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में बीते दो माह में सवा पाँच लाख युवाओं को विभिन्न योजनाओं में रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्म-निर्भर बनने का अवसर दिया गया है। प्रतिमाह एक लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने और आर्थिक उन्नयन का लाभ देने के लक्ष्य के मुकाबले दोगुनी उपलब्धि प्राप्त हुई है। प्रतिमाह ढाई लाख लोगों को लाभान्वित करने में सफलता मिली है। अब प्रत्येक माह रोजगार दिवस मनाया जाएगा। हमारे नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिले, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में रोजगार दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर तथा म.प्र. कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज स्वामीविवेकानंद जयंती पर स्वामी जी के इस कथन से प्रेरणा लेना चाहिए कि- "मनुष्य यदि निश्चय कर ले और रास्ता बना ले तो कोई कार्य असंभव नहीं है।" स्वामी जी का वास्तविक नाम नरेन्द्र था, भारत के लिए भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने कहा था कि आने वाली सदी भारत की होगी। आज एक और नरेन्द्र (प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी) के नेतृत्व में भारत वैभवशाली और गौरवशाली राष्ट्र बनकर विश्व गुरू के रूप में पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री जमशेद जी टाटा की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि वे छोटे से कार्य को प्रारंभ कर इतने बड़े उद्योगपति बने। मजबूत संकल्प से युवा अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य सफल होंगे।

दो माह में सवा पाँच लाख को योजनाओं में मिला लाभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में प्रयास बढ़ाए गए हैं। गत 15 नवम्बर 2021 से 12 जनवरी 2022 की अवधि में प्रदेश में 5 लाख 26 हजार 510 युवाओं को लाभान्वित करने का ठोस कार्य हुआ है। हमारा प्रयास ऐसी शिक्षा प्रदान करना है, जो रोजगार भी उपलब्ध करवाए। नई शिक्षा नीति में भी संपन्न भारत के निर्माण की कल्पना है। कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान से यह स्पष्ट होता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं के हाथ में कौशल हो और उन्हें जीविका मिले, यह बहुत आवश्यक है। मध्यप्रदेश के नौजवान अब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। वास्तव में युवा नया इतिहास रच सकते हैं।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

नवीन क्षेत्रों में हो सहकारिता का उपयोग - मुख्यमंत्री

सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाएँ भू-माफिया किसी का प्लाट न हड़पें, सहकारिता विभाग न्याय दिलवाए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गैर पारम्परिक क्षेत्रों में सहकारिता के उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्रामीण परिवहन सेवा, खाद्य प्र-संस्करण, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहकारिता का अच्छा उपयोग हो सकता है। विभाग में कम्प्यूटर के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाए। बड़े नगरों में गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का कार्य भी निरंतर किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को सक्षम बनाने अभियान को भी गति देना जरूरी है। यह समितियाँ सहकारिता को बढ़ाने का आधार हैं। इनसे जुड़े कर्मचारियों को उपयोगी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के आव्हान और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में सहकार से समृद्धि के भाव को अंगीकार कर

नवीन सहकारी नीति तैयार की जाए। जिन जिला सहकारी बैंकों का परफार्मेंस बेहतर नहीं है, उन्हें निरंतर शासकीय अंशपूँजी देने का औचित्य नहीं है। अन्य राज्यों के सहकारी क्षेत्र में हुए अच्छे कार्यों का मध्यप्रदेश में भी अनुसरण किया जाए।

नए-नए क्षेत्रों में हो सहकारिता का उपयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि और पशुपालन के साथ ही नए-नए क्षेत्रों में सहकारिता का उपयोग किया जाए।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्रदेश के सहकारी साख आन्दोलन में अपेक्स बैंक की भूमिका

भोपाल। मध्यप्रदेश के सहकारी साख आन्दोलन को सफल बनाने में समन्वयक की भूमिका के रूप में प्रदेश स्तर पर म.प्र. राज्य सहकारी बैंक अपनी 24 शाखाओं एवं जिला स्तर पर 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको तथा प्राथमिक स्तर पर अपनी 4523 पैक्स (प्राथमिक सहकारी साख समितियों) के माध्यम से कृषि एवं सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के जनकल्याण के लिए सहकारी भावना से समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहा है एवं सहकारी साख के सतत विस्तार के लिए भारतीय रिर्जव बैंक, नाबार्ड एवं म0प्र0शासन के सहकारिता विभाग के दिशा–निर्देशों से सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ व पारदर्शी बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में म.प्र. शासन के निर्देशों को क्रियान्वित करने की दिशा में सहकारिता विभाग के नोडल एजेंसी बनने पर समन्वयक के रूप में अपेक्स बैंक द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको एवं प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण एवं विभिन्न कृषि आदानों का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ता सामग्री वितरण यथा केरोसीन, खाद्यान का वितरण भी संपूर्ण प्रदेश में किया जाता हैं, कृषको की फसल के उचित मूल्य हेतु उपार्जन का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा हैं। कोविड–19 महामारी के समय में प्रदेश में लॉकडाउन होने के बावजूद सहकारी समितियों ने विषम परिस्थतियों में 45. 93 लाख किसानों से गेहूँ का 4527 उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जन किया। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार अपेक्स बैंक द्वारा समन्वयक के रूप में मध्यप्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से गेहूँ ,चना,सरसों,एवं मसूर की खरीदी का रिकॉर्ड बनातें हुये वर्ष 2020–2021 में 1 करोड़ 29 लाख टन गेहूँ के साथ 8 लाख 23 हजार टन चना, सरसों और मसूर की भी खरीदी की गई। लगभग 17 हजार उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीणों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। वर्ष 2020–2021 में समर्थन मूल्य अन्तर्गत कुल 1404 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 5.86 लाख किसानों से 37.26 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो कि पिछले वर्षो की तुलना में धान की रिकार्ड खरीदी रही हैं। वर्ष 2021–22 में समर्थन मूल्य अन्तर्गत 7.25 लाख किसानों से 428.56 लाख मैट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की गयी हैं। किसानों की सुरक्षा के लिए कोविड सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के अलावा उनकी सुविधाये हेतु इस

वर्ष मेकेनाइज्ड ग्रेन क्लीनिंग एवं ग्रेडिंग मशीनों की भी व्यवस्था चिन्हित उपार्जन केन्द्रों पर की गई ताकि किसानों से मानक क्वालिटी का गेहूँ खरीदा जा सके। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधा हेतु छायादार स्थान , पंखा, छत्री, स्वच्छ पेयजल एवं सेनिटरी सुविधायें उपलब्ध हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दिशा –निर्देशो एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी की प्रदेश के सहकारी साख आंदोलन को मजबूत एवं पारदर्शी बनाने की कल्पना को साकार रूप देने हेतु शीर्ष बैंक प्रबंधन प्रदेश में कार्यरत त्रि–स्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के माध्यम से सुदृढ़ किये जाने की दिशा में भी निरंतर प्रयत्नशील हैं। इस वर्ष प्रदेश के लगभग 12 लाख कृषको को प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से 0 प्रतिशत ब्याज दर पर रू0 750.44 करोड़ का फसल ऋण उपलब्ध कराया गया है, जो गतवर्ष की समान अवधि से लगभग 57 प्रतिशत अधिक हैं। 2021–22 में कृषकों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से 4.47 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उपलब्ध कराया गया तथा 37.92 लाख कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया। म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक प्रबंधन ने उक्त कार्यों के क्रियान्वयन के साथ ही बैंक की प्रगति तथा विकास हेतु ग्राहको को त्वरित एवं उत्तम बैंकिंग की सुविधायें प्रदान किये जाने की दिशा में कई निर्णय लिये तथा प्राथमिकता के आधार पर कालातीत ऋणों की वसूली हेतु भी कार्ययोजना बनायी, जिनकी वसूली में कठिनाई आ रही थी। अपेक्स बैंक के प्रशासक एवं सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक ,सहकारी संस्थाये मध्यप्रदेश श्री नरेश पाल कुमार जी के निर्देशन एवं प्रबंध संचालक श्री पी.एस. तिवारी के अथक प्रयासों से अन्य बैंको से प्रतिस्पर्धा एवं व्यक्तिगत ऋण व्यवसाय में वृद्धि को ध्यान में रखकर ऋणों पर ब्याज दरों को कम किया गया । वर्तमान में अपेक्स बैंक द्वारा केन्द्र शासन , राज्य शासन ,शासकीय निगम , मण्डल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंको संस्थाओं एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियमित कर्मचारियों को आवास ऋण ,उपभोक्ता ऋण , व्यक्तिगत ऋण , वाहन ऋण , उच्चशिक्षा ऋण, भ्रमण ऋण, चिकित्सा ऋण ,त्यौहार ऋण एवं अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण सुविधा मात्र 8.00 प्रतिशत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अपेक्स बैंक विगत अनेक वर्षो से लाभ की स्थिती मे हैं। इस वर्ष के दौरान बैंक ने लगभग राशि रू0 73.87 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया हैं।

अपेक्स बैंक के डेस्क कैलेण्डर का विमोचन

भोपाल। अपेक्स बैंक के डेस्क कैलेण्डर का विमोचन नरेश पाल कुमार, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश एवं प्रशासक, अपेक्स बैंक, पी.एस.तिवारी, प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, संयुक्त आयुक्त गण सहकारिता अरविंद सिंह सेंगर, बृजेश शुक्ल, अनिल वर्मा, श्री अभय खरे, संजय दलेला एवं नाबार्ड मध्यप्रदेश के उप महाप्रबंधक कंवर जावेद द्वारा सुभाष यादव समन्वय भवन टी.टी. नगर भोपाल में किया गया। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के प्रदेश भर से आये संयुक्त/उप/सहायक आयुक्तों के साथ अपेक्स बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी श्रीमती अरूणा दुबे, के.के. द्विवेदी , अरविंद बौद्ध, सहायक महाप्रबंधक डा. रवि ठक्कर, आरएस चंदेल, के.टी. सज्जन व जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित थे। इस कैलेण्डर में मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अवकाश एवं बैंको के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत निर्धारित अवकाश के साथ अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश किया गया हैं।

भूमाफिया की नकेल कसने बनेगी नई सहकारिता नीति : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपना मकान हर व्यक्ति का सपना होता हैं। किसी व्यक्ति की जीवन भर की कमाई को कोई भू–माफिया न हड़पे इसके लिये नई सहकारी नीति बनाएं। सहकारिता विभाग के अधिकारी भू–माफिया के सताये लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। इसमें कोई वैधानिक अड़चन हैं तो उसका भी रास्ता निकाला जा सकता हैं। श्री चौहान ने सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान अपने विचार व्यक्त किये। विभागीय समीक्षा बैठकों के मैराथन क्रम में दूसरे दिन भी उन्होंने आठ विभागो की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की गड़बड़ियो पर रोक लगी हैं, लेकिन भविष्य में ये लोगों को सता न सकें इसके लिए दीर्घकालिक उपाय करने की जरूरत हैं।

किसानो से खरीदी करने वाली संस्थाओ की होगी भरपाई

कैबिनेट ने लिया निर्णय

भोपाल। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने वाली दो संस्थाओ को राज्य सरकार कर्ज से उभरने के लिए मदद करेगी। इसके लिए राज्य सरकार उपार्जन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी, जिससे कि वह संस्थायें बगैर किसी परेशानी के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी करती रहे। इससे किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

कैबिनेट ने प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी हैं। इस निर्णय के बाद म.प्र. में किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने वाली दो संस्थाएं म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ व म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को फायदा होगा। निर्णय के तहत योजना में उपार्जन कार्य करने वाली राज्य की विभिन्न ऐजेसियों की हानि तथा प्रतिपूर्ति के संबंध में मापदंड नियत करने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इसमें खाद्य सहकारिता कृषि पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं वित्त विभाग के अधिकारी शामिल होगें। प्रदेश में धान, गेहूँ, मूंग, सहित अन्य फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाता हैं। उपार्जन का काम यही दो संस्थाएं करती हैं यह दोनों ही संस्थाएं खरीदी के चलते कर्ज लेती हैं। ज्यादातर कर्ज आरबीआई से लिया जाता हैं। इस समय नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड पर लगभग 73 हजार करोड़ रूपये से अधिक की देनदारी बाकी हैं। यह दोनों संस्थाएं पहले खरीदी करती हैं। उसके बाद जब उपज को सेंट्रल पूल में लिया जाता हैं तब केन्द्र सरकार राशि का भुगतान करती हैं। इस प्रकिया में इन संस्थाओ को केंन्द्र से राशि मिलने में दो से तीन वर्ष तक की देरी हो जाती हैं।

मध्यप्रदेश कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में लाएगा श्रेष्ठ परिणाम

योजनाओं में दी गई स्वीकृतियों के लिये माना आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान –कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्रियो को मध्यप्रदेश के लिए योजनाओं में दी गई स्वीकृतियो के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर को मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और उनके फॉलोअप की जानकारी दी उन्होंने विशेष रूप से कृषि विविधीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासो की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में ठोस कार्य कर श्रेष्ठ परिणाम सामने लाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलेट मिशन, खाद्य और कृषि उत्पादो के प्रसंस्करण कार्य को गति देने की योजना तैयार हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती और मुख्य फसलों गेहूँ, चना, धान, और सोयाबीन के अलावा चंदन की खेती और बांस उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधाएं देकर प्रेरित किया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के प्रति मध्यप्रदेश को सतत् पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार से निरंतर मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

अब सहकारिता के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे उद्योग

भोपाल। सहकारिता के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आर्थिक विकास के मॉडल को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार नवाचार करने जा रही हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वे स्थानीय मांग पर आधारित होंगे। इससे रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होंगे ही आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके लिए पहले सर्वे कराया जाएगा और फिर सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। इनका काम उत्पादन तक सीमित रहेगा। विपणन का जिम्मा जिला स्तरीय समितियां संभालेगी। ये समितियां ही प्राथमिक समितियों को कच्चा माल भी उपलब्ध करायगी। जो साम्रगी तैयार होगी उसकी बिक्री का इतंजाम जिला स्तर पर किया जाएगा और जो साम्रगी बचेगी उसे राज्य स्तर पर बिकवाने के प्रयास किये जायेंगे। यह काम ग्रामीण और औद्योगिकीरण महासंघ करेगा। इसका पंजीयन 31 मार्च 2022 के पहले होगा और फिर प्राथमिक सहाकारी समितियां बनेंगी। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और आर्थिक विकास को मद्देनजर रखते हुए सहकारिता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रो में सहकारी समितियां बनाने का निर्णय किया है। दरअसल, प्रत्येक ग्राम में कुछ न कुछ ऐसा काम होता है, जिसे व्यापारिक दृष्टिकोण से संगठित करके किया जाये तो न सिर्फ उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल सकता है बल्कि रोजगार के अधिक अवसर भी बनेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग ने ग्रामीण औद्योगिकीकरण महासंघ बनाने का निर्णय किया हैं। इसके बाद ग्राम स्तर पर सर्वे कर उद्योग स्थापित करने सहकारी समिति गठित की जायेगी। इसमे यह देखा जाएगा की उद्योग स्थापित होने से कितने लोगो को रोजगार मिलेगा और जो उत्पादन होगा, उसकी खपत कहां और कैसे होगी। उद्योग की स्थापना के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं से सहायता और बैंक से ऋण दिलाया जायेगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योग की स्थापना में केन्द्र सरकार की कृषि अधोसंरचना निधि के तहत भी परियोजना स्वीकृत कराने के प्रयास किये जायेंगे।

प्रधानमंत्री के किसान -कल्याण के संकल्प की सिद्धि के लिए मिलकर करेंगे प्रयास : चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के शिरडी धाम में प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसान सम्मान निधि की 10 वीं किश्त के अंतरण के अवसर पर उनके उद्बोधन का वर्चुअल श्रवण किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहां कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए जो संकल्प लिये हैं उनकी सिद्धि के लिए मैं और मध्यप्रदेश के किसान मिलकर हरसंभव प्रयास करने के लिए सकंल्पित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गयी पी. एम. किसान सम्मान निधि योजना में नए साल के पहले दिन 10वीं किश्त के रूप में देश के 11 करोड़ 37 लाख किसानो को 20 हजार करोड़ की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी का हृदय से आभार माना हैं।

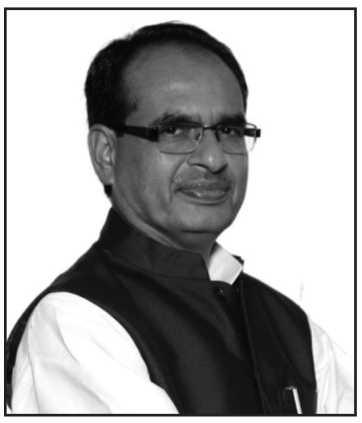

जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास : श्री चौहान ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में विगत गई वर्षों से जैविक खेती को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है और 2020–21 में जैविक उत्पादों का ढाई हजार करोड़ रूपये से अधिक का निर्यात हुआ है। साथ ही किसानों की उन्नति के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे है। किसानों को मुख्यमंत्री किसान–कल्याण योजना में 4 हजार रूपये प्रति वर्ष 2 किश्तों में सम्मान निधि और जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज एवं कृषि यंत्रो की खरीदी के लिए सहायता राशि दी जा रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण में मध्यप्रदेश देगा हरसंभव योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए अंकुर अभियान में पौध –रोपण एवं सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहां कि पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प की सिद्धि के लिए मध्यप्रदेश अपना हरसंभव योगदान देगा ।

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ के मंत्र ने दी नई ऊर्जा। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ के मंत्र ने देश को नई ऊर्जा दी हैं। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में शिखर प्राप्त कर रही हैं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री मोदी को जाता है। मध्यप्रदेश में बेटियों के लिए लाड़ली लक्ष्मी सहित कई प्रभावशाली योजनाएं जारी हैं।

भारत ने रचा इतिहास पहली बार भारतीय बना आईसीए-एशिया प्रशांत का अध्यक्ष, सांसद चंद्रपाल यादव को मिली जिम्मेदारी

सहकारिता के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की हैं। डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA & International Cooperative Aliance) एशिया प्रशांत के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। सियोल (साउथ कोरिया) में आयोजित चुनाव में उन्होने जीत दर्ज की । इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बना हैं। इस चुनाव में यादव को 185 वोट मिले जबकि जापान से उनकी प्रतिद्वंदी चितोस अराय को केवल 83 बोट मिले भारत की सौ से अधिक मतों से जीत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी राजनीति में बड़ी बात हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) की गर्वनिंग काउंसिल सदस्य डॉ. यादव इस बार मैदान में थे। इंटरनेशनल को–आपरेटिव एलायंस (आईसीए) एक विश्व स्तरीय सहकारी महासंघ हैं, जो दुनिया भर में सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता हैं। इसकी स्थापना 1895 में दुनिया भर में सहकारी समितियों को एकजुट करने के लिए की गई थी। इस समय 112 देशों के कुल 318 सहकारी संगठन इसके सदस्य हैं। जिनके जरिये यह संगठन दुनिया भर में करीब एक अरब व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हैं।

एलांयस के सदस्य कृषि, बैंकिग,उपभोक्त, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और श्रमिकों सहित अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में काम करते हैं। सहकारी समितियां अपने सदस्स्यों के स्वामित्व वाले मूल्य आधारित व्यवसाय है, चाहे वे ग्राहक हों, कर्मचारी हो या निवासी, सदस्यों को व्यवसाय में समान अधिकार और लाभ का हिस्सा मिलता हैं। आईसीए में 20 सदस्यीय शासी बोर्ड, एक महासभा , चार क्षेत्र (अफ्रीका, यूरोप, एशिया–प्रशांत और अमेरिका के लिए एक–एक) क्षेत्रिय संगठन और विषयगत समितियां शामिल हैं।

डॉ. यादव अपने गांव में प्राथमिक सहकारी समितियों से शुरू होकर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के अध्यक्ष के पद तक पहुॅचने के 30 वर्षो से अधिक समय से भारतीय सहकारिता आंदोलन के अग्रणी नेता हैं। यादव ने पड़ोसी देशो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता की हैं। सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में मलेशिया और अन्य देशों के साथ सहयोग को भी मजबूत किया है।

श्री चंद्रपाल यादव को ऐतिहासिक कामयाबी के लिए दिल्ली स्टेट को–आपरेटिव यूनियन लि0 एवं सभी सहकारी समितियों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

"एक जिला-एक उत्पाद" योजना को गंभीरता से लें : मुख्यमंत्री श्री चौहान

उद्यानिकी से जुड़े किसानों को दिलवायें प्रशिक्षण ● नर्सरियों को डिमांड ड्रिविन बनायें

मसाला फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों को दें बढ़ावा
●
मुख्यमंत्री ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उद्यानिकी विभाग "एक जिला-एक उत्पाद" योजना को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी से जुड़े किसानों को चिन्हित उत्पाद की खेती के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उद्यानिकी, खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्सरियों को डिमांड ड्रिविन बनाना चाहिये। उन्होंने कहा कि जिन पौधों की माँग होती है, नर्सरियों में ऐसे पौधों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिये। विभाग द्वारा बताया गया कि उद्यानिकी नर्सरियों को पीपीपी मोड पर विकसित किया जा रहा है। इस योजना में स्व-सहायता समूह के माध्यम से 137 उद्यानकी नर्सरी स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया और अन्य मसाला फसलों के उत्पादन में प्रदेश का देश में अग्रणी स्थान है। मसाला फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों को बढ़ावा देना चाहिये। मसाला फसलों की प्र-संस्करण इकाइयाँ भी लगाना चाहिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्यानिकी फसलों को संरक्षित रखने के लिये कोल्ड-स्टोरेज लगाने पर भी जोर दिया। साथ ही उद्यानिकी किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती से जोड़ने की बात भी कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्यानिकी विभाग द्वारा बुंदेलखण्ड के किसानों को पान की खेती से जोड़ने के कार्यक्रम की सराहना भी की। विभाग द्वारा एक हजार किसानों को पान की खेती से जोड़ा जा रहा है।

बताया गया कि 20 आदर्श विकासखण्डों में शत-प्रतिशत गिरदावरी की जायेगी। गिरदावरी से उत्पादन, खपत और बचत का आकलन करना संभव होगा। इससे भण्डारण क्षमता का निर्माण और प्र-संस्करण इकाइयाँ स्थापित करने में सुगमता होगी। अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण श्री जे.एन. कंसोटिया ने वर्चुअली शामिल होकर उद्यानिकी विभाग के आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोड मैप में सम्मिलित कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर ढंग से करने के लिये विभाग द्वारा 179 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही ग्वालियर में 20 हेक्टेयर भूमि पर अटल फ्लोरीकल्चर गार्डन की स्थापना की जा रही है।

ग्रेडिंग के आधार पर प्रदेश की पंचायतें होंगी पुरस्कृत : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की पंचायतों के कार्य की ग्रेडिंग की जायेगी तथा जो पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा। हर पंचायत की विकास योजना बनाई गई है, उस पर अमल कर 'स्मार्ट विलेज' बनाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभाग द्वारा गाँव-गाँव में कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिये बनाये गये 'मोबाइल एप' का लोकार्पण भी किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, सीईओ मध्यप्रदेश डे राज्य आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा 127 "दीदी कैफे" संचालित किये जा रहे हैं। ये स्वल्पाहार केन्द्रों के रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। आने वाले समय में वल्लभ भवन, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि स्थानों पर भी "दीदी कैफे" खोले जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक कचरा निपटान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। गाँव-गाँव से प्लास्टिक कचरा संग्रहण की व्यवस्था की गई है, जहाँ से प्लास्टिक कचरा संग्रहण केन्द्रों तक पहुँचेगा और वहीं से इसकी बिक्री होगी। प्रदेश में 28 प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र खोले जा रहे हैं, जिनका संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जायेगा। प्रदेश में लगभग 9 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 42 हजार से अधिक पुरानी जल-संरचनाओं के पुनउर्द्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह कार्य मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से कराया जा रहा है। इससे बड़े क्षेत्र में सिंचाई, मछली-पालन, सिंघाड़ा उत्पादन आदि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में समुदाय आधारित ग्रामीण पर्यटन में "होम-स्टे" योजना सफलता से संचालित की जा रही है। योजना के प्रति पर्यटकों में अच्छा उत्साह दिख रहा है। निवाड़ी जिले के लदपुरा ग्राम तथा पन्ना जिले के मदला ग्रामों में 'होम-स्टे' में बड़ी संख्या में पर्यटक रुक रहे हैं। योजना की सफलता के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी संबंधितों को बधाई दी गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर गाँव के इतिहास, गौरव, पहचान, संस्कृति, महापुरुषों आदि को पुन: स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक गाँव में हर वर्ष "ग्राम स्थापना दिवस" मनाया जायेगा। उन्होंने आगामी अप्रैल माह से इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये।

हमारे उत्पाद "जैम" और "अमेजन" पर बिकें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों एवं अन्य द्वारा तैयार किये गये उत्पाद जैम पोर्टल एवं अमेजन जैसे मार्केटिंग प्लेटफार्म पर बिकें, इसके लिये सघन प्रयास किये जायें।

समूहों को ऋण स्वीकृति में प्रदेश देश में प्रथम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूहों को ऑनलाइन माध्यम से ऋण प्रकरण प्रस्तुत करने तथा ऋण स्वीकृति में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा है। वर्ष 2021-22 में एक लाख 40 हजार 576 ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये। स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण की त्वरित कार्यवाही के लिये मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिये।

हर गाँव में हो ग्राम संगठन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में हर गाँव में ग्राम संगठन बनें। वर्तमान में प्रदेश में 32 हजार 874 ग्राम संगठन हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी 45 हजार गाँवों में ग्राम संगठन बनाने के निर्देश दिये।

74 प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास पूर्ण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2024 तक सभी को आवास दिये जाने का लक्ष्य है। योजना में प्रदेश को 30 लाख 39 हजार आवास का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध प्रदेश में 29 लाख 78 हजार (97.3 प्रतिशत) आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 22 लाख 65 हजार (74 प्रतिशत) आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास

(शेष पृष्ठ 5 पर)

गाँव में पदस्थ हों तकनीकी कार्यों में दक्ष इंजीनियर : मुख्यमंत्री श्री चौहान

पेयजल योजनाओं में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को प्रोत्साहन और विलंब करने वालों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

- विशेष ग्राम सभाओं में घोषित होंगे "हर घर जल" ग्राम
- गाँव-गाँव और घर-घर तक पीने का पानी पहुँचाने प्रधानमंत्री श्री मोदी को ग्रामवासी भेजेंगे आभार-पत्र
- जल जीवन मिशन योजना में मध्यप्रदेश प्रथम
- प्रदेश में 4019 ग्राम बने हर-घर जल श्रेणी के ग्राम, देश में तृतीय क्रम पर
- डेढ़ वर्ष में 27.65 लाख परिवारों तक पहुँचा शुद्ध पेयजल
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए निर्मित रोडमैप में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रदेश में समस्त नलजल योजनाओं के कार्य सम्पन्न हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं के बेहतर संधारण के लिए ग्राम इंजीनियर पदस्थ किए जाएँ। उन्होंने वृहद परियोजना के कार्यों में समय पर कार्यों की पूर्णता के लिए संबंधित एजेंसी और अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विलंब से होने वाले कार्यों पर जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। नलजल योजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर ग्रामों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर ग्राम को "हर घर जल" श्रेणी का ग्राम घोषित किया जाएगा। योजना के निर्माण कार्य पूरे होने पर संबंधित पंचायत को योजना हस्तांतरित की जाएगी। ग्राम जल और स्वच्छता समिति के पदाधिकारी ग्रामवासियों से जन-संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी को ऐसी महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना लागू करने के लिए ग्रामवासियों द्वारा आभार-पत्र भी भेजे जायेंगे।

(पृष्ठ 4 का शेष)

ग्रेडिंग के आधार पर प्रदेश .....

के हितग्राहियों को शासन की 36 प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इनमें राशन प्रदाय, नल-बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाएँ शामिल हैं।

सभी गाँवों को 'ओडीएफ-प्लस' बनाना है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी गाँवों को 'ओडीएफ-प्लस' बनाना है। इसमें सभी घरों में शौचालय, 80 प्रतिशत घरों में कम्पोस्ट पिट, 80 प्रतिशत घरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा सभी ग्रामों में प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथकीकरण कार्य किये जाने हैं। प्रदेश के 1154 गाँव को अभी तक 'ओडीएफ-प्लस' बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये हैं कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये कि नये बनने वाले घर बिना शौचालय के न हो।

ग्राम सड़क निर्माण में प्रदेश देश में प्रथम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में शीर्ष पर है। योजना से प्रदेश की 17 हजार 541 बसाहटों को जोड़ा जाना था, जिसके विरुद्ध 17 हजार 506 (99.80 प्रतिशत) बसाहटों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश के 250 एवं इससे अधिक जनसंख्या के जनजातीय ग्राम तथा 500 एवं अधिक जनसंख्या के अन्य सभी ग्राम प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ गये हैं।

मनरेगा के भुगतान में न हो विलंब

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि मनरेगा में कराये गये कार्यों के भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिये। उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह से बातचीत कर लंबित भुगतान के लिये बजट की माँग की। केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त कराया कि शीघ्र ही बजट दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना, पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, देवारण्य योजना के संचालन, पोषण-आहार संयंत्रों के हस्तांतरण आदि के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये।

ग्राम स्तर पर पदस्थ हों तकनीकी जानकार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम स्तर पर ऐसे ग्रामीण इंजीनियर को तैनात किया जाए जो विद्युत कनेक्शन, पेयजल प्रदाय व्यवस्था, सिंचाई पम्पों से संबंधित प्रबंध, आवास निर्माण के तकनीकी पहलुओं आदि की जानकारी रखता हो। पम्प और वाल्व ऑपरेटर का प्रशिक्षण कुछ ही दिनों में दिया जा सकता है। रोजगारविहीन युवाओं को इन कार्यों के लिए तीन छह माह के छोटे प्रशिक्षण कोर्स का लाभ दिलवाकर ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना और अन्य योजनाओं में मेन्टेनेंस का दायित्व सौंपा जाए। मध्यप्रदेश में इस क्षेत्र में एक मॉडल तैयार कर उसके क्रियान्वयन की पहल हो। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग की भूमिका का निर्वहन करे। बड़े ग्रामों में एक से अधिक युवक भी यह जिम्मेदारी वहन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में पेयजल व्यवस्था

अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव ने प्रेजेंटेशन में बताया कि तीन वर्ष के रोडमैप में मध्यप्रदेश में मार्च 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा जल प्रदाय की उपलब्धता 30.55 प्रतिशत हो गई थी, जो वर्तमान में 37.10 प्रतिशत है। इसे राष्ट्रीय औसत 45.57 प्रतिशत तक लाने और इससे भी अधिक उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य है। प्रदेश में विभिन्न नलजल योजनाओं पर 42 हजार 643 करोड़ रूपए की राशि खर्च हो रही है। गत वित्त वर्ष में 26 लाख घरों तक पेयजल कनेक्शन के मुकाबले 19 लाख 89 हजार घरों में कनेक्शन दिए गए जो लक्ष्य का तीन चौथाई है। वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी लगभग 122 लाख ग्रामीण परिवारों तक पेयजल उपलब्धता के लक्ष्य के मुकाबले गत दिसम्बर तक 45 लाख 10 हजार लाख परिवारों तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। अगले तीन माह में 52 लाख 62 हजार लाख परिवारों तक पेयजल उपलब्ध होगा। नल और बिजली से जुड़े मरम्मत कार्यों के लिए 50 हजार मैकेनिक आगामी तीन वर्ष में प्रशिक्षित करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण आईटीआई और अन्य संस्थाएँ प्रारंभ कर चुकी हैं। जल जीवन मिशन में ग्राम और एफएचटीसी (फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन) कार्य-योजना में 25 हजार 399 ग्रामों की समूह नल जल योजना में 9 हजार 351 कार्य प्रगति पर हैं। कुल 26 हजार 186 ग्रामों की एकल ग्राम नल जल योजना में 8 हजार 176 कार्य प्रगति पर हैं। यह व्यवस्था भी की गई है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सड़क खुदाई की अनुमति के लिए कांट्रेक्टर जल निगम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा। यह अनुमति अलाइनमेंट परीक्षण के बाद प्रदान की जायेगी और उसके बाद ही कांट्रेक्टर रोड कटर का उपयोग करेगा। पाइप लाइन डालने के बाद कांट्रेक्टर द्वारा सड़क की आवश्यक मरम्मत करवाई जायेगी। सड़क को पूर्वास्था में लाने के लिए योजना की डीपीआर में प्रावधानित राशि का भुगतान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश है सबसे आगे

भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में केन्द्रांश-राज्यांश की राशि के व्यय में मध्यप्रदेश 2,790 करोड़ की राशि का उपयोग कर प्रथम स्थान पर है। हर घर जल उपलब्ध करवाने में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहां 4,019 ग्राम में यह सुविधा दिलवाई जा चुकी है। प्रदेश में मई 2020 से वर्तमान तक 27 लाख 65 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। इस अवधि में प्रदेश में नल से जल का प्रतिशत 14.5 से बढ़ाकर 37.10 प्रतिशत तक पहुँचाया गया। मध्यप्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहाँ समस्त जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएँ एनएबीएल (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज) प्रमाणित हैं। मिशन से तेजी से क्रियान्वय के लिए प्रदेश के बजट में वर्ष 2020-21 में इस कार्य के लिए तीन गुना अधिक राशि दी गई। चालू वित्त वर्ष में देश में मध्यप्रदेश को सबसे पहले प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रांच राशि 1247 करोड़ प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रमुख निर्देश

- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभियंता नियमित दौरे करें, रिपोर्ट भी दें।
- पूर्ण योजनाओं का विधिवत लोकार्पण हो,आमजन को जानकारी मिले।जागरूकता भी बढ़ेगी।
- बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य समय पर पूरा करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए।
- क्रियान्वयन में देर के लिए दोषी दण्डित होंगे।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामों में पूर्ण पेयजल योजना पंचायत को विधिवत सौंपी जाए।

फूलों की खेती को बढ़ावा दे रही मोदी सरकार...

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए दी ये सलाह

●

आय में वृद्धि करने के लिए वैल्यू एडिशन भी करना होगा. इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनाना चाहिए व प्रोसेसिंग से भी जुड़ना चाहिए.

पुणे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुणे स्थित भारतीय पुष्प अनुसंधान संस्थान में बुनियादी सुविधा के रूप में प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होने कहा कि किसान भाई-बहन आय बढ़ाने के लिए फूलों की खेती की ओर रुझान करें. आय में वृद्धि करने के लिए वैल्यू एडिशन भी करना होगा. इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनाना चाहिए व प्रोसेसिंग से भी जुड़ना चाहिए.

तोमर ने आगे कहा कि फूलों की आवश्यकता देश की परंपराओं, धार्मिक-सामाजिक-राजनीतिक आदि आयोजनों के अनुसार आज भी है. फूलों के व्यापार में एक्सपोर्ट के नजरिए से भी काफी गुंजाइश है. वहीं हमारे देश की विविध जलवायु इतनी समृद्ध है कि फूलों की खेती काफी फलफूल सकती है. उन्होंने किसानों को फूलों के वैल्यू एडेड उत्पादों जैसे गुलाब में गुलकंद और अन्य फूलों के उत्पादों को समयानुरूप परिवर्तित करने व मार्केट बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया. ताकि इससे आय बढ़ सके.

तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं बनवाई हैं. जिसका किसानों को लाभ मिल रहा है. इसके साथ-साथ किसानों को तकनीकी रूप से भी मजबूत होना होगा. फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है. उन्होंने वेस्ट् टू वैल्थि मिशन का जिक्र किया, साथ ही कहा कि कृषि उत्पाद वैश्विक मानकों पर खरे उतरने वाले होने चाहिए.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च के माध्यम से खेती को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि युवा इस ओर आकर्षित हों. नए रोजगार का सृजन हो सके. तोमर ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि नई किस्मों के विकास व अनुसंधान में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फूलों की सुगंध कम नहीं हो, क्योंकि खुशबू का अपना ही महत्व है.

(पृष्ठ 1 का शेष)

नवीन क्षेत्रों में हो सहकारिता का उपयोग - मुख्यमंत्री

मत्स्य पालन, बकरी पालन, ग्रामीण परिवहन सेवा, हेल्थ सेक्टर, पर्यटन, विभिन्न खाद्य उत्पादों के प्र-संस्करण कार्य में सहकारिता से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। सहकारिता के पहुँच और उसके व्यापक प्रभाव को समझते हुए इसके लिए रोडमैप तैयार करें।

परिश्रम से अर्जित पूँजी और भू-खंड को भू-माफिया न हड़पें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बड़े नगरों में गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं पर नियंत्रण हुआ है। लेकिन इसके लिए एक ऐसी दीर्घकालिक नीति का निर्माण किया जाए, जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवनभर की परिश्रम से अर्जित पूँजी व्यर्थ न जाए। ऐसे प्रकरणों में विभाग स्तर पर होने वाली कार्यवाही में यदि कोई वैधानिक अड़चनें हों, तो उसका रास्ता भी निकाला जाए। सहकारिता विभाग प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से पीड़ित और परेशान नागरिकों को न्याय दिलवाये।

विभाग के प्रयास

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण और किसानों को उनके द्वारा किए गए उत्पादन की अधिकतम कीमत दिलवाने के लिए अधो-संरचनात्मक विकास के कार्य किए गए हैं। एग्री इन्फ्रा फंड में 124 पैक्स में ग्रेडिंग सार्टिंग यूनिट स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार) में 107 करोड़ की लागत से 145 गोदाम मंजूर किए गए हैं। मनरेगा में 314 प्लेटफार्म निर्मित कर लिए गए हैं। इसके अलावा 797 प्लेटफार्म निर्माणाधीन हैं। विभाग और सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया गया है। ऑनलाइन सोसायटी पंजीयन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। सहकारी बैंकों में नियुक्ति की कार्यवाही भी की जा रही है। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना में गत वर्ष लगभग 30 लाख कृषक लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्त वर्ष में 13 हजार 707 करोड़ रूपये का ऋण वितरण गत 24 दिसम्बर 2021 तक हुआ है। वर्ष 2022-23 के लिए 17 हजार करोड़ रूपये का लक्ष्य प्रस्तावित है। गत माह ही द्वितीय अनुपूरक अनुमान द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 500 करोड़ रूपए की शासकीय अंशपूँजी देने का प्रावधान किया गया है। मार्कफेड को इस राशि से उपार्जन और खाद व्यवसाय के लिए बिना ब्याज की राशि उपलब्ध हो जाने पर सुविधा होगी।

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी उपस्थित थे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

आत्म-निर्भर भारत बनाने में....

कोरोना काल में भी प्रदेश में निवेश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना काल में भी निवेश आया है। टेक्सटाइल उद्योग सहित भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए पृथक-पृथक कलस्टर बनाए जा रहे हैं। सस्ती जमीन और अन्य सुविधाओं का लाभ नई इकाइयों की स्थापना के लिए दिया जा रहा है। सीहोर बुधनी के लकड़ी के कलात्मक खिलौने, भोपाल के बटुए, जनजातीय बहुल जिलों से कोदो-कुटकी सहित अन्य उत्पाद लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी लोकल उत्पाद को वोकल बनाने का आव्हान कर चुके हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नयन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूह की महिलाओं को ग्रामीण आजीविका मिशन में 12 लाख बहनों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों केलिए दो हजार करोड़ रूपए की क्रेडिट लिंकेज का लाभ दिया गया। यह उपलब्धि ऐतिहासिक है।

बेकलॉग के पदों की पूर्ति और अन्य विभागों में पदों के लिए चयन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में बेकलॉग के पदों की पूर्ति और नवीन पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। आयुष चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, सहायक, कौशल प्रशिक्षण अधिकारी, जेल प्रहरी, उप यंत्री के पदों के साथ ही सहकारिता और अन्य विभाग में पदों पर चयन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

विभिन्न क्षेत्रों से रोजगार सृजन और आर्थिक उन्नयन के प्रयास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में सहकारिता, कृषि, खनिज और पर्यटन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। मध्यप्रदेश का प्रसिद्ध शरबती गेहूं एमपी व्हीट के नाम से दुनिया में लोकप्रिय है। "एक जिला-एक उत्पाद" में सभी जिले के उत्पादों का चयन कर उनके अधिक से अधिक विक्रय के प्रयास किए जा रहे हैं। वनों से समृद्धि हासिल करने के प्रयास हो रहे हैं। देवारण्य योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। वनोत्पाद की प्रोसेसिंग के पश्चात औषधि निर्माण के कार्य को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में 89 जनजातीय विकासखंडों में स्थानीय युवाओं को ही खाद्यान्न वितरण का दायित्व दिया गया है। कुसुम योजना में सोलर पैनल की स्थापना से आर्थिक उन्नयन का मार्ग आसान हुआ है। ग्रामीण और शहरी आजीविका योजनाओं से भी युवा लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाभान्वित युवाओं को बधाई दी और विभिन्न योजनाओं में ऋण राशि की स्वीकृति के लिए बैंकों का भी आभार व्यक्त किया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग आगामी 2 साल में 30 लाख रोजगार सृजित करेगा। मध्यप्रदेश में क्लस्टर आधारित उद्योगों का सुनियोजित विकास किया जा रहा है और इसी दिशा में इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर 500 एकड़ भूमि पर प्रारम्भ किया गया है। इस क्लस्टर से 20 हज़ार युवाओं को सीधे और 30 हज़ार को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। भोपाल सहित ग्वालियर, नीमच और बैतूल में 4 फर्नीचर क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। मध्यप्रदेश अकेला ऐसा राज्य होगा जहाँ कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बहुत कम अवधि में 5 लाख 26 हज़ार युवाओं को रोजगार दिया गया है। प्रदेश में खिलौना क्लस्टर के विकास में तेजी से काम चल रहा है। इस क्लस्टर में अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने भी रुचि दिखाई है। इसके लिए 30 तकनीकी लब से करारनामा किया गया है, जिससे नव उद्यमियों को तकनीकी कौशल उपलब्ध हो सके। विभिन्न जिलों में जल्दी ही सेमिनार आयोजित कर इन उद्यमियों को सपोर्ट किया जाएगा। स्टार्ट अप पॉलिसी को भी जल्द ही अंतिम रूप देंगे।

हितग्राहियों को हितलाभ वितरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न योजना के हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान कर उनसे संवाद भी किया। इनमें भोपाल की श्रीमती कौशर जहाँ, श्री आनंद कुमार जैन, श्री अशोक थापा, श्री अनिल भसमे, श्रीमती पुष्पा बाई, श्रीमती रश्मिता गरई, विदिशा के श्री शानू चौबे और होशंगाबाद के श्री शैलेष बरकुर शामिल हैं। श्रीमती कौशर जहाँ को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में दो लाख की राशि रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय के लिए मिली है। विदिशा के श्री शानू चौबे को इसी कार्यक्रम में बेल्डिंग वर्क के लिए दस लाख की राशि प्रदान की गई। इन्होंने आठ अन्य को रोजगार भी दिया है। होशंगाबाद के शैलेष बरकुर ने साढ़े नौ लाख की प्राप्त सहायता से बिजली सामग्री का व्यवसाय शुरू किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से श्री अशोक थापा ने फास्ट फूड सेंटर प्रारंभ किया है। श्री अनिल भसमे को स्टेशनरी शॉप के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में ऋण दिया गया है। श्रीमती पुष्पा बाई को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में दस हजार की राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व-रोजगार से जुड़ रहे सभी हितग्राहियों को भी बधाई दी।

हितग्राहियों से किया संवाद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों में रोजगार मेले में लाभान्वित हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। बालाघाट के हितग्राही श्री विनोद बर्वे को टेंट डेकोरेशन, नीमच के श्री नीलेश पाटीदार को सीमेंट और पेवर ब्लॉक निर्माण, रीवा के श्री पार्थ पाण्डे को बेकरी प्रोडक्ट्स, ग्वालियर के श्री अली अहमद को गुड़ बूरा और इलायची दाना निर्माण और टीकमगढ़ की अनीता सोनी को खिलौना शॉप प्रारंभ करने की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से संवाद के दौरान बैंक से मिले ऋण और उनके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन सभी युवाओं को व्यवसाय में सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

सचिव और उद्योग आयुक्त श्री पी. नरहरि ने स्वागत भाषण में रोजगार दिवस तथा रोजगार मेलों में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। रोजगार दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर भी हुआ।

किस योजना से कितना लाभ

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 लाख 87 हजार 55 हितग्राहियों को 2,97 करोड़ रूपये।
- पीएम स्वनिधि योजना में 57 हजार 125 हितग्राहियों को 71 करोड़ रूपये।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 691 समूहों और 12 हजार 156 बहनों को 192 करोड़ रूपये।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 1602 हितग्राहियों को 20 करोड़ रूपये।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में 63 हजार 764 हितग्राहियों को 63 करोड़ रूपये।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 4 हजार 117 हितग्राहियों को 107 करोड़ रूपये।

मध्यप्रदेश में सोया इण्डस्ट्रीज के विकास के प्रयास बढ़ाएंगे – मुख्यमंत्री

360 करोड़ लागत के एकीकृत सोया प्र-संस्करण और पशुधन फीड संयंत्र का भूमि-पूजन

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में सोया इण्डस्ट्री को स्थापित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। किसानों के हित में सोया इण्डस्ट्रीज को फिर से खड़ा करना है। सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की बिक्री और प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना से किसानों को लाभ दिलवाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। प्रयाय यह करेंगे कि किसानों के परिश्रम का उन्हें भरपूर मूल्य मिले, इसलिए निर्यात के क्षेत्र में भी प्रयास बढ़ाए जाएंगे। वर्तमान में सोया ऑयल का आयात बढ़ने से राष्ट्र की पूँजी का व्यय हो रहा है। इस नाते सोया प्र-संस्करण इकाइयों की शुरूआत मायने रखती है। किसानों से कच्चा माल लेकर उनके प्रोडक्ट का वेल्यू एडिशन कर उन्हें लाभ दिलवाने के लिए ऐसी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम खैरवास में करीब 360 करोड़ की लागत के सोया प्लांट के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आईबी ग्रुप के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअली भागीदारी की। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मौके पर प्लांट का भूमि-पूजन किया। लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले इस संयंत्र का कार्य अगले 18 माह में पूर्ण होगा। करीब 3000 मेट्रिक टन की क्षमता से उत्पादन होगा। स्थानीय किसानों को सोयाबीन फसल के पर्याप्त दाम मिलेंगे।

किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के परिश्रम से मध्यप्रदेश को सात बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब हम कृषि से खाद्य प्र-संस्करण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्यप्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। उनके संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे प्लांट सहायक होंगे जो किसानों को लाभान्वित करेंगे। प्रदेश में उत्पादन वृद्धि, लागत घटाने, उचित मूल्य दिलवाने की व्यवस्था के साथ शून्य प्रतिशत पर ऋण जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। पूर्व में भावांतर योजना के माध्यम से भी किसानों को बाजार से फसल के मूल्य के अंतर की राशि उपलब्ध करवाई गई। सोया प्र-संस्करण इकाई के लिए मध्यप्रदेश का चयन उचित भी है, क्योंकि उपभोक्ताओं को खाद्य तेल भी कम कीमत पर मिलेगा और सोयाबीन उत्पादक कृषक भी लाभान्वित होंगे। इस तरह की इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए भी नए निवेश आवश्यक हैं। मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए समय-समय पर नीतियों में भी संशोधन किया गया है।

पीला सोना कहलाता है सोयाबीन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 11 जलवायु क्षेत्र हैं। मध्यप्रदेश गेहूँ के उत्पादन और गुणवत्ता के मामले में विश्व विख्यात है। गेहूँ उत्पादन में हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह दलहन, तिलहन उत्पादन में हम आगे आ गए हैं। यही नहीं फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों के उत्पादन में भी मध्यप्रदेश प्रगति कर रहा है। एक समय सोयाबीन में भी मध्यप्रदेश नंबर एक पर था। इसे पीला सोना कहते हैं। किसानों की आर्थिक हालत बदलने का काम किया था, लेकिन फसलों की क्षति भी काफी होती थी। इस संबंध में कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। प्रदेश में तीन शासकीय और छह निजी विश्वविद्यालय कृषि अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं।

सिंचाई ने पलटी है काया, बदनावर को मिलेगा नर्मदा जल का लाभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पहले 6 से 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। गत 18 वर्ष में इसकी वृद्धि 43 लाख हेक्टेयर तक हो गई है। हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर का है। शासकीय और निजी साधनों से करीब एक करोड़ आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। भरपूर सिंचाई से ही मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र में देश में अग्रणी प्रांतों में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस संयंत्र की स्थापना से विशेष रूप से बदनावर क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। यहाँ सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी। पर्याप्त नर्मदा जल का लाभ भी बदनावर को मिले इसके प्रयास किए जाएंगे।

कोरोना काल में भी आया निवेश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निवेश के लिए मध्यप्रदेश सबसे अनुकूल राज्य है। यहाँ औद्योगिक शांति के साथ पर्याप्त भूमि की उपलब्धता भी है। प्रदेश के नागरिक सहयोगी स्वभाव के हैं। यहाँ निवेशकों के लिए हितैषी उद्योग प्रोत्साहन नीति है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2021-22 के प्रारंभिक 9 महीनों में 27 हजार 856 करोड़ रूपए का नवीन निवेश आया है। करीब 70 हजार लोगों के लिये प्रत्यक्ष रोजगार की राह खुली है।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और सोयाबीन जैसे उत्पादन को उपयोग में लाने के लिए प्र-संस्करण इकाई की शुरूआत हो रही है। सोयाबीन के रकबे में वृद्धि होगी साथ ही स्थानीय किसान लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में श्री राजेश अग्रवाल, श्री खेमराज पाटीदार और अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

किसान भाई चिंता न करें, सरकार संकट में उनके साथ है : कृषि मंत्री श्री पटेल

खेतों में जाकर ली फसल क्षति की जानकारी, हर सम्भव मदद का दिलाया भरोसा

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के कुछ ग्रामों में गत रात्रि में हुई ओलावृष्टि की खबर लगते ही सुबह किसानों से ओला वृष्टि से हुई फसल क्षति संबंधी जानकारी ली और राज्य सरकार की ओर से हर सम्भव मदद एवं राहत दिलाने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी गाँव-गाँव का दौरा कर सर्वे कर रहे हैं। सही जानकारी प्राप्त कर, उसके आधार पर किसानों को राहत दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि 72 घण्टे की समय-सीमा में सर्वे कराकर कलेक्टर द्वारा उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाए ताकि किसानों को फसल बीमा योजना की 25 प्रतिशत राशि तत्काल मिल सके।

कलेक्टर के साथ ग्रामों का किया दौरा

कृषि मंत्री श्री पटेल ने फसल क्षति की खबर लगते ही कलेक्टर श्री संजय गुप्ता और उप संचालक कृषि श्री चन्द्रावत के साथ पानतलाई, बालागाँव और अन्य प्रभावित गाँवों में खेतों में जाकर फसल नुकसानी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा का लाभ भी मिलेगा और राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों में किसानों को पात्रता अनुसार फसल क्षति राहत राशि यथाशीघ्र दिलाई जाएगी। मंत्री श्री पटेल ने भ्रमण के दौरान किसानों से कहा कि वे बिल्कुल चिंता न करें, प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ है।

किसानों के लिए सस्ती दर पर होगा शहद प्रसंस्करण

देश की पहली 'मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन' लांच

नई दिल्ली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लांच की। मोबाइल वैन का डिजाइन 15 लाख रूपये की लागत से केवीआईसी ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र, पंजोखेड़ा में आंतरिक रूप किया है। यह मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट 8 घटों में 300 किग्रा तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। यह वैन जांच प्रयोगशाला से भी सुसज्जित है जो तत्काल शहद की गुणवत्ता की जांच कर सकती है।

इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि शहद मिशन का उद्देश्य देश में शहद का उत्पादन बढ़ाना और किसानों तथा मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि यह नवोन्मेषी मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करेगी। मधुमक्खी पालकों के लिए शहद निकालने तथा प्रसंस्करण की लागत में कमी लाने के अतिरिक्त, यह शहद में किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका को समाप्त कर देगी क्योंकि प्रसंस्करण मधुमक्खी पालकों एवं किसानों के दरवाजों पर ही किया जाएगा। यह शहद प्रसंस्करण यूनिट उन छोटे किसानों एवं मधुमक्खी पालकों के लिए एक वरदान साबित होगी जिन्होने अपने शहद को प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग के लिए अन्य शहरों में ले जाने पर अतिरिक्त लागत उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर, विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसी और मोबाइल हनी प्रोसेसिंग इकाइयां आरंभ की जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि प्रसंस्करण संयंत्रों तक शहद को ले जाना छोटे किसानों तथा मधुमक्खी पालकों के लिए एक

खर्चीला मामला है। उच्च परिवहन लागत तथा प्रसंस्करण के खर्च से बचने के लिए, अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को अपने फार्म पर ही बहुत कम कीमत पर एजेटों को बेच देते थे। इसके परिणामस्वरूप, ये मधुमक्खी पालक मधुमक्खी पालन के वास्तविक मौद्रक लाभों को अर्जित करने में सक्षम नहीं हो पाते थे। इस मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इन राज्यों की विभिन्न मधुवाटिकाओं में जाएंगी, जहां मधुमक्खी पालक अपने शहद को मामूली शुल्क पर प्रसंस्कृत कराने में सक्षम हो पाएंगे और वह भी उनके दरवाजों पर ही। इस शहद प्रसंस्करण इकाई में शहद की जांच करने के लिए एक प्रयोगशाला टेक्निशियन तथा एक तकनीकी सहायक भी शामिल रहते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि शहद मिशन के तहत, केवीआईसी ने अभी तक देश भर में लगभग 1.60 लाख मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया है और 40,000 से अधिक रोजगारों का सृजन किया है। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ही जहां वनस्पतियों की प्रचुरता है, केवीआईसी ने किसानों तथा मधुमक्खी पालकों को लगभग 8000 मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं जिससे उनकी आय कई गुना बढ़ गई है और अंत:परागण के जरिये फसल की ऊपज में बढोतरी हुई है।

गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन पर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं सहकारी निरीक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। सहकारी संस्थाओं में गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर दिनांक 03.01.2022 से 05.01.2022 तक कुल 24 प्रतिभागियों ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की व्याख्या एवं प्रावधान विषय पर श्री डी. के. सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा/अधिवक्ता, वर्तमान में प्रदेश में प्राप्त महत्वपूर्ण गबन अपराधियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं अपराध पूर्व रोकथाम, विषय पर श्री अविनाश सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं दस्तावेज व गबन, धोखाधडी, अमानत में खयानत आदि प्रकरणों का न्यायालयीन निर्णय हेतु प्रमुख तथ्य समस्या एवं समाधान विषय पर पर श्री के के सक्सेना, से.नि. डिप्टी डायरेक्टर, प्रोसिक्यूशन , संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों का परीक्षण, तकनीकी पैरामीटर के आधार पर– सी.आर., ए.आर., एन.पी.ए. एवं अन्य पैरामीटर पर कर प्रतिवेदन दर्ज करना विषय पर श्री पी.के.एस. परिहार, वरिष्ठ प्रबंधक अपेक्स बैंक, संस्थाओं के अंकेक्षण में सी.बी.एस. एवं डी.एम. आर. एकाउंट का परीक्षण करना एवं वित्तीय अनियमित्ताओं की जानकारी प्राप्त करना विषय पर श्री आर.के. गंगेले, ओ.एस.डी., अपेक्स बैंक, संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों के परीक्षण–निरीक्षण एवं टैक्स लायबलिटी (जी.एस.टी., आयकर आदि) का परीक्षण एवं अंकेक्षण टीप में शामिल किया जाना विषय पर सुश्री परमवीर कौर, चार्टड एकाउंटेंट, सहकारी संस्था को हुई हानि की पूर्ति हेतु की जाने वाली विधिक कार्यवाही एवं पृथक वैधानिक प्रतिवेदन की जानकारी व कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यनिष्पादन, कर्तव्य, उत्तरदायित्व व प्रशासक निर्वाचन अधिकारी, परिसमापन, अंकेक्षण विषय पर श्री श्रीकुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता, सहकारी संस्थाओं में गबन एवं धोखाधडी के मुख्य प्रकार एवं उनके तथ्यों का प्रकटीकरण पर श्री प्रदीप नीखरा सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता, वर्तमान में संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु जारी अद्यतन परिपत्र एवं उनका पालन कर वित्तीय अनियमितताओं पर रोकथाम विषय पर श्री संजीव गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, व्यक्तित्व विकास, संवैगात्मक बुद्धि, समय एवं तनाव प्रबंधन विषय पर श्री राजेन्द्र सक्सेना, कारपोरेट मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर श्री संजय सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी , राज्य संघ के द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इस कार्यक्रम का संचालन श्री गणेश प्रसाद मांझी , प्राचार्य के द्वारा किया गया। श्री विनोद कुशवाहा, श्री लोकेश श्रीवास्तव, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री धनराज सैंदाणे, श्री ज्ञानू सिंह एवं समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।